Issue-2 | May : 2023

FJCCI MEDIA

FEDERATION OF JHARKHAND CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

फेडरेशन ऑफ झारखण्ड चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज



ARYAN GROUP™
Where Your Dreams Comes True

ARYAN DEVELOPER AND REALTOR PVT. LTD.

ASHASHREE HEIGHTS
MORABADI, RANCHI



BOOKINGS OPEN

JAGANNATH GARDENS
PUNDAG T.O.P., RANCHI



ARYAN ENCLAVE
TUPUDANA, RANCHI



ACHYUT ENCLAVE
TUPUDANA, RANCHI



7631199906, 7631199912

Address:- 2nd Floor, Arctic Mall, Bariatu Road, Ranchi
Email:- info@aryangroup.in | Website:- www.aryangroup.in

अध्यक्षीय उद्बोधन



FJCCI के निरंतर प्रयास से झारखण्ड में भवन नियमितीकरण योजना जल्द प्रभावी की जा रही है। योजना के प्रत्येक बिंदु को व्यवहारिक बनाते हुए नगर विकास विभाग द्वारा इसे प्रभावी किया जा रहा है जिससे अधिकाधिक राज्यवासी लाभान्वित होंगे। FJCCI द्वारा दिसंबर माह में दिये गये सुझावों के अतिरिक्त कुछ अन्य सुझावों को भी समाहित करने की स्वीकृति नगर विकास विभाग द्वारा दी गई है। यह सुझाया गया है कि वैसे भवन जिनकी उंचाई 15 से 21 मीटर तक है, उन्हें भी अधिभार शुल्क लेकर नियमितीकरण करने का प्रावधान किया जाय और Plinth area को 500 Sq. mtr. से 600 Sq. mtr. कर दिया जाय। होल्डिंग टैक्स में कमी करने के हम सभी के एक अन्य महत्वपूर्ण प्रयास में भी सफलता मिली है। सरकार के निर्णयानुसार राज्य के व्यवसायिक भवन का होल्डिंग टैक्स 30% तथा शैक्षणिक और धार्मिक स्थलों पर 70% तक कमी की गई है। सरकार के इस निर्णय से विशेषकर धर्मशाला, चैरिटी संस्थान जो समाज सेवा के कार्यों में संलग्न हैं लाभान्वित होंगे। कैबिनेट के इस निर्णय से लोगों में उत्साहजनक स्थिति बनी हुई है।

साथियों, राज्य में कृषि मण्डी शुल्क प्रभावी करने के निर्णय के विरोध में FJCCI के नेतृत्व में राज्यस्तर पर किये गये आंदोलन में सफलता प्राप्त हुई है। इस क्रम में राज्यस्तरीय बैठक के साथ ही अनिश्चितकालीन खाद्यान्न व्यापार बंद का निर्णय भी हमें लेना पड़ा। अंत में सरकार के साथ संपन्न वार्ता के दौरान प्राप्त सकारात्मक आश्वासन पर इस आंदोलन को स्थगित किया गया। राज्य सरकार के साथ ही आप सभी की सहयोगात्मक भूमिका के कारण FJCCI द्वारा राजधानी रांची में लगाये गये दस दिवसीय इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर का सफल संचालन भी संभव हो सका है। फेयर को राज्यस्तरीय स्वरूप दिये जाने के हमारे प्रयास में भी हमें उत्साहजनक सफलता मिली है। जीएसटी से पूर्व के बकाया विवादों जैसे सेल्स टैक्स, वैट, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, इंट्री टैक्स इत्यादि के वर्षों पुराने विवाद के निपटारे हेतु राज्य सरकार द्वारा कर समाधान योजना 31 मई तक प्रभावी है। योजना के तहत सेटलमेंट एमाउंट काफी आकर्षक है, जिसका लाभ हम सभी व्यापारियों को अवश्य लेना चाहिए। प्रदेश में MSME इकाईयों के विकास के लिए उद्योग विभाग के साथ नियमित रूप से समीक्षा बैठकों का दौर जारी है। लघु इकाईयों की सुविधा के लिए यह सुझाया गया है कि औद्योगिक क्षेत्र में 5 हजार से 20 हजार वर्गफीट तक के छोटे-छोटे भूखण्ड उपलब्ध करायें जायें। इसी प्रकार औद्योगिक क्षेत्र में आवंटित भूखण्ड की 30 वर्ष की लीज अवधि को पुनः 99 वर्ष के लिए करने के हमारे सुझाव पर भी स्वीकृति दी गई है। MSME उद्योगों की सुविधा हेतु चैंबर भवन में जल्द ही सप्ताह में दो दिन सिडबी और MSME विभाग द्वारा हेल्पडेस्क लगाया जाना आरंभ किया जा रहा है। उद्यमी इस सुविधा का अधिकाधिक लाभ लें। अंत में, FJCCI MEDIA के प्रकाशन कार्य में संलग्न टीम को बधाई। मुझे उम्मीद है कि इस पत्रिका के अंक में व्यापार जगत के अनुकूल सूचनाओं के प्रकाशन से आप सभी लाभान्वित होंगे। संगठन ही शक्ति है। आपका चैंबर, सबका चैबर। चैंबर को सशक्त बनाने हेतु आपका साथ और समर्थन की आवश्यकता है।

भवदीय,
किशोर मंत्री
अध्यक्ष

संपादकीय...



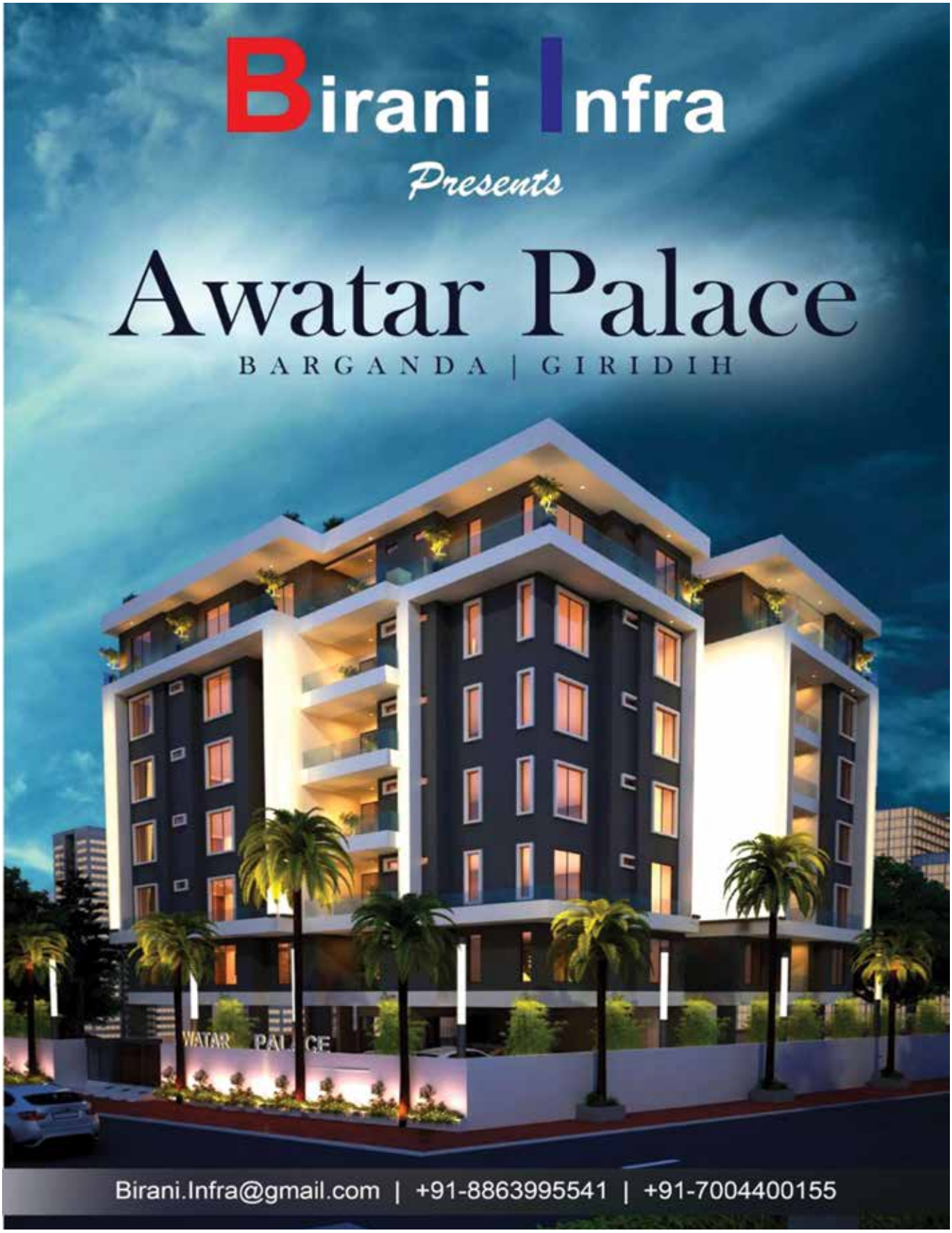
कतिपय कारणों से FJCCI MEDIA के इस अंक के प्रकाशन में विलंब अवश्य हुआ है किंतु इसमें प्रकाशित सूचनाएं आपके लिए उपयोगी हों, जानकारी से पूरिपूर्ण हों, इसका हमने विशेष ख्याल रखा है। पत्रिका को आकर्षक बनाने के लिए सदस्यों की ओर से प्राप्त सुझाव को भी हमने विशेष प्राथमिकता दी है। प्रसन्नता है कि आपने हमारी टीम द्वारा प्रकाशित पूर्व के अंक के लिए हमारा उत्साहवर्द्धन करते हुए मार्गदर्शन किया है। पत्रिका के इस अंक में प्रमण्डलीय गतिविधियों का संकलन भी किया गया है, जो काफी आकर्षक है। हमें उम्मीद है संबंधित प्रमण्डल के सदस्य भी हमारे इस प्रयास से



सतुष्ट होंगे। पत्रिका में अपेक्षित सुधार के लिए पुनः आपके सुझाव आमंत्रित हैं। आपसे यह भी आग्रह है कि आप अपने क्षेत्र में होनेवाली व्यवसायिक गतिविधियों के साथ ही अपने लेख एवं रचनाएं हम तक तक अवश्य प्रेषित करें ताकि हम उन्हें पत्रिका के आगामी अंकों में शामिल कर सकें।

अभिषेक अग्रवाल
चेयरमेन, FJCCI MEDIA
मो. : +91 94311 75315

सुनिल सरावगी
चेयरमेन, FJCCI MEDIA
मो.: +91 76315 55555


Birani Infra
Presents
Awatar Palace
BARGANDA | GIRIDIH
Birani.Infra@gmail.com | +91-8863995541 | +91-7004400155

उपाध्यक्ष की कलम से...



सुखद है कि भवन नियमितीकरण योजना के हमारे प्रयासों पर नगर विकास विभाग द्वारा कार्रवाई आरंभ कर दी गई है। होल्डिंग टैक्स में कमी के हमारे सुझावों पर भी राज्य सरकार द्वारा सकारात्मक निर्णय लिया जा रहा है। इन योजनाओं के जल्द क्रियान्वयन से राज्यवासियों की समस्याओं का समाधान संभव होगा। झारखण्ड में औद्योगिकीकरण को गति देने के उद्देश्य से बंद पडी खदानों को जल्द खोलने की दिशा में भी हमारा प्रयास जारी है।

आदित्य मल्होत्रा
उपाध्यक्ष



FJCCI की गतिविधियों के आयोजन में उप समिति चेयरमेन की सहभागिता उत्साहजनक है, इससे कई व्यापारिक जटिलताओं का सरलीकरण संभव हो रहा है। मई माह में FJCCI द्वारा दस दिनों तक इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर का सफल आयोजन किया गया। फेयर में राज्य सरकार के साथ ही 15 राज्यों और 9 अंतराष्ट्रीय देश की सकारात्मक भूमिका रही। फेयर की अपार सफलता को देखते हुए अगले वर्ष पुनः इसका आयोजन वृहद् स्तर पर किया जायेगा।

अमित शर्मा
उपाध्यक्ष

सह सचिव का संदेश...



अनाधिकृत निर्माण को नियमितीकरण करने की प्रक्रिया शीघ्र आरंभ हो, इस हेतु FJCCI द्वारा निरंतर बैठकों का दौर जारी है। सुखद है कि माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा रांची नगर निगम और आरआरडीए से नक्शा पास करने पर लगी रोक हटा दी गई है। न्यायालय के इस फैसले के बाद रांची और आसपास के लोगों को बडी राहत मिलेगी। पिछले पांच माह से नक्शा पास करने पर लगी रोक के कारण आम लोगों के साथ ही डेवपलर्स, रियल एस्टेट कारोबारी और मजदूर प्रभावित हो रहे थे।

रोहित पोद्दार, सह सचिव



FJCCI के प्रदेश स्तर पर जिलों के दौरे से व्यापार जगत में विश्वसनीयता का माहौल बन रहा है। हमारे इस प्रयास से कई जिलों में चैंबर ऑफ कॉमर्स और व्यवसायिक संघ का गठन संभव हुआ है। राजधानी रांची के मुख्य व्यवसायिक केंद्र अपर बाजार की यातायात समस्या के समाधान के साथ ही निगम द्वारा आवंटित दुकानों के किराया विवाद का समाधान भी संभव होने की दिशा में अग्रसर है।

शैलेष अग्रवाल, सह सचिव

कोषाध्यक्ष की कलम से...



फेडरेशन के प्रति सदस्यों का परस्पर जुडाव और गतिविधियों में साकारात्मक उपस्थिति उत्साहवर्द्धक है। सदस्यता संख्या में वृद्धि, व्यापारिक जटिलताओं का सरलीकरण और FJCCI को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में हमारा प्रयास निरंतर जारी है। इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर की अपार सफलता के बाद पूर्व निर्धारित कार्य योजनाओं पर हमारा प्रयास जारी है। प्रसन्नता है कि FJCCI की मेम्बर्स डायरेक्टरी का प्रकाशन कार्य भी अंतिम चरण में है, जो जल्द ही सदस्यों के बीच वितरित किया जायेगा।

सुनिल केडिया, कोषाध्यक्ष

पूर्व अध्यक्ष की कलम से...



भारत की आर्थिक गतिविधियाँ वैश्विक महामारी के बावजूद भी नहीं थमी, निरंतरता जारी है। कई कड़े और बड़े निर्णय लिये गये। इस वर्ष के बजट को भी देखें तो जो वर्ग, जो क्षेत्र, पिछड़े हैं उनके लिये विशेष ध्यान, इन्फ्रास्ट्रक्चर पर 7 से बढ़कर 9 लाख करोड़ के खर्च का प्रावधान, रिसर्च के निवेश इत्यादि नयी सोच, जो एक समय सीमा में, भारत को विकसित देशों की कतार में खड़ा करने का है। इस दिशा में उठाये गये कदमों की निरंतरता है।

5 विलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में धन तो काफी होगा, अवसर भी काफी होंगे, तकनीकी पर जोर होगा, बदलाव जरूर होगा। खुशी है भारत का व्यापारी वर्ग भी पीछे नहीं। झारखण्ड भी पीछे नहीं रहेगा, राज्य सरकार की और सजगता चाहिये। आशा है चेम्बर भी बदली परिस्थिति में अपने सदस्यों की आकांक्षाओं को पूरा कर सकेगा।

शुभकामना !

सधन्यवाद

-महेश पोद्दार,
पूर्व सदस्य, राज्यसभा सह पूर्व अध्यक्ष - FJCCI



FJCCI MEDIA, चैंबर कार्यकारिणी का सदस्यों के साथ संपर्क, गतिविधियों की सूचना पहुंचाने तथा विविध कानूनों में बदलाव की जानकारी देने का सशक्त माध्यम है। मुझे खुशी है कि वर्तमान कार्यकारिणी श्री किशोर मंत्री जी की अगुवाई में यह काम कुशलतापूर्वक कर रही है। पूर्व अध्यक्षों को पत्रिका के माध्यम से सदस्यों को जोडने का कार्य प्रशंसनीय है। श्री किशोर मंत्री जी जिस प्रकार फ्रंटलाइन से कार्यसमिति को मोबलाइज कर रहे हैं, वे बधाई के पात्र हैं। मेरा सदस्यों से अनुरोध है कि समस्या के समाधान के लिए चैंबर की गलती निकालने के बजाय सहयोग करें तभी चैंबर भी आपकी मदद कर सकता है। सदस्यों और कार्यकारिणी समिति को अनेकानेक शुभकामनाएं।

-के.के. साबू, पूर्व अध्यक्ष,
फेडरेशन ऑफ झारखण्ड चैंबर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज

पूर्व क्षेत्रीय उपाध्यक्ष की कलम से...



फेडरेशन ऑफ झारखण्ड चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज बहुत अच्छा काम कर रही है और इस काम के बल पर ही यह झारखण्ड की प्रतिनिधि व्यापारिक संस्था बन गयी है। इसके लिए फेडरेशन एवं इसके पदाधिकारी बधाई के पात्र हैं। मेरी तरफ से फेडरेशन और इसके पदाधिकारियों को बहुत-बहुत बधाई।

गोविंद प्रसाद डालमिया
भूतपूर्व उपाध्यक्ष



FJCCI का बढ़ता स्वरूप राज्य के स्टेकहोल्डर्स के बेहतरी के अनुकूल है। फेडरेशन की गतिविधियों में सदस्यों की दिन प्रतिदिन बढ़ती सहभागिता देखकर काफी प्रसन्नता हो रही है। FJCCI द्वारा हर एक नियमित अंतराल पर किये जा रहे विभिन्न जिलों के दौरे से व्यापारियों का विश्वास बढ़ रहा है। संगठन को मजबूती देने के लिए सदस्यता संख्या में विस्तार आवश्यक है, जिस दिशा में वर्तमान कार्यसमिति बेहतर प्रयास कर रही है। उम्मीद है संतोषजनक है कि व्यापारिक कानूनों व लाइसेंसी जटिलताओं के सरलीकरण की दिशा में FJCCI सतत प्रयत्नशील है। चैंबर पत्रिका के माध्यम से पूर्व अध्यक्षों और कई वरीय सदस्यों की सहभागिता के लिए अध्यक्ष श्री किशोर मंत्री जी की योजना सराहनीय है। सलाह है कि पत्रिका में फेडरेशन की गतिविधियों के साथ-साथ ऐसा रूप दें कि वह हमारे प्रदेश में सरकार की नीतियों के निर्धारण का भी एक सशक्त माध्यम बन सके।

-ओमप्रकाश अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष
फेडरेशन ऑफ झारखण्ड चैंबर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज

पूर्व क्षेत्रीय उपाध्यक्ष की कलम से...



खुशी की बात है कि चेम्बर FJCCI MEDIA का दूसरा संस्करण जल्द ही निकालने जा रही है यह अच्छी पहल है। पत्रिका से हमारे सदस्य चेम्बर के द्वारा किये गये कार्यों के बारे में जान पाते हैं।

FJCCI MEDIA से जानकारी मिली कि चेम्बर अध्यक्ष श्री किशोर मंत्री बहुत ही सकारात्मक कार्य कर रहे हैं। चेम्बर की सभा राँची से बाहर भी बुलायी जा रही है तथा पूरे झारखण्ड की समस्याओं को सुनकर उसे दूर करने की कोशिश की जा रही है।

मेरा मानना है कि FJCCI सरकार के साथ विचार-विमर्श हमेशा करती रहती है। अतः चेम्बर सरकार को राज्य की आधारभूत संरचना (INFRASTRUCTURE), कानून-व्यवस्था तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर अधिक से अधिक ध्यान दिलवाये तो राज्य में व्यापार और उद्योग का जाल बिछ जायेगा और राज्य के विकास को कोई रोक नहीं सकता।

FJCCI अध्यक्ष श्री किशोर मन्त्री अपनी टीम और सदस्यों को भावनाओं को समझते हुए उन्हें साथ लेकर काम कर रहे हैं। इसलिए चेम्बर का भविष्य उज्जवल है।

मैं पूरी टीम को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ।

गोविन्द लाल अग्रवाल
पूर्व उपाध्यक्ष, रामगढ़

चैंबर की गतिविधियाँ.....



डॉ. अभिषेक रामाधीन
महासचिव

जनहित में कृषि शुल्क विधेयक की वापसी का निर्णय व्यापार जगत के साथ ही कृषकों एवं आम उपभोक्ताओं के लिए उत्साहवर्धक है। इस विधेयक के विरोध में FJCCI द्वारा आहूत राज्यस्तरीय आंदोलन में निर्णायक भूमिका के लिए सभी सदस्यों का आभार। FJCCI के सुझाव पर बिल्डिंग रेगुलराइजेशन स्कीम, ट्रांस्पोटर्स के अनुकूल ट्रांस्पोर्ट नगर निर्माण की प्रक्रिया, शहर में नो-इंट्री संबंधित समस्या, अपर बाजार की पार्किंग व्यवस्था के समाधान के साथ ही बाजार क्षेत्र में निगम द्वारा आवंटित दुकानदारों की समस्या के समाधान की दिशा में निगम द्वारा प्रयास आरंभ कर दिये गये हैं। डिलर्स की समस्याओं के समाधान हेतु राज्यस्तरीय जीएसटी सलाहकार समिति की बैठकों का आयोजन प्रारंभ करने, पंडरा बाजार को मतगणना केंद्र बनाये जाने के जिला प्रशासन के निर्णयों पर पुनर्विचार करने तथा उद्योग विभाग और स्टेकहोल्डर्स की समीक्षात्मक बैठकों के आयोजन की दिशा में भी फेडरेशन द्वारा प्रयासों को गति दी गई है। FJCCI MEDIA के इस अंक में जनवरी से मई मध्य तक की प्रमुख गतिविधियों का संक्षिप्त ब्यौरा उल्लिखित है। प्रमुख गतिविधियों का एक संक्षिप्त सारांश आपके सूचनार्थ प्रस्तुत है:-

बाजार शुल्क विधेयक पर क्रमवार प्रयास



झारखण्ड में कृषि शुल्क विधेयक को प्रभावी करने के सरकार के प्रयास पर पुनर्विचार हेतु FJCCI द्वारा नियमित रूप से उच्चस्तरीय बैठकें की गईं। माननीय मंत्री श्री आलमगीर आलम, विभागीय सचिव अबुबकर सिद्दीकी से वार्ता के साथ ही विधायिका श्रीमती दीपिका पांडे सिंह, कांग्रेस पार्टी के स्थानीय नेता श्री अजयनाथ शाहदेव, श्री आदित्य विक्रम जयसवाल, श्री कुमार राजा, श्री संजय पाण्डेय, श्री ज्योति मथारू, झारखण्ड प्रभारी श्री अविनाश पाण्डेय एवं पार्टी के वरीय नेता सह सांसद श्री शशि थरूर से दिल्ली में भी वार्ता की गई। यह सुझाया गया कि झारखण्ड के वातावरण को देखते हुए आम उपभोक्ता, किसान, प्रसंस्करण उद्योग एवं राज्यहित में मार्केटिंग बोर्ड एवं सभी बाजार समितियों को भंग कर दिया जाय। हमें सभी से साकारात्मक आश्वासन मिलने के उपरांत कार्रवाई नहीं होने पर राज्यस्तरीय बैठक का आयोजन कर राज्यव्यापी अनिश्चितकालीन खाद्यान्न व्यापार बंद का निर्णय लिया गया।

बाजार शुल्क विधेयक के विरोध में सफल प्रयास



आप अवगत हैं कि झारखण्ड में कृषि शुल्क विधेयक को प्रभावी करने के कृषि मंत्री के निर्णय का विरोध करते हुए FJCCI द्वारा फरवरी माह में क्रमवार प्रयासों को गति दी गई। इस दौरान रांची में राज्यस्तरीय बैठक, माननीय विधायकों के साथ वार्ता, कृषि मंत्री के साथ ही अन्य मंत्रिगणों के साथ बैठक, सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन, धरना, पोस्टकार्ड अभियान, स्थानीय विधायक और कृषि मंत्री का घेराव के साथ ही राज्य में चार दिनों तक खाद्यान्न व्यापार बंद किया गया। हमारे इस आंदोलन का विभिन्न व्यापारिक संगठनों का समर्थन भी रहा। चार दिनों तक चले खाद्यान्न व्यापार बंद से उत्पन्न हुई समस्या के उपरांत माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्यमंत्री सचिवालय में कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री के सचिव श्री विनय चौबे के साथ FJCCI के पदाधिकारियों की बैठक हुई। सकारात्मक आश्वासन के उपरांत सभी जिलों के चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों की सहमति से राज्यव्यापी खाद्यान्न व्यापार बंद को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। इस आशय को और मजबूत बनाने के लिए पुनः कृषि मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री से भी वार्ता की गई। माननीय मुख्यमंत्री ने व्यापारियों से अपील करते हुए कहा कि कृषि शुल्क को लेकर व्यापारी चिंतित नहीं हों। सरकार ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगी जिससे राज्य के व्यापारी, किसान और उपभोक्ता प्रभावित हों।

कृषि विधेयक पर माननीय राज्यपाल से हस्तक्षेप का आग्रह



झारखण्ड में कृषि शुल्क विधेयक को प्रभावी करने के निर्णय को शिथिल करने के लिए FJCCI के पदाधिकारियों ने तत्कालीन माननीय राज्यपाल श्री रमेश बैश से मुलाकात की। माननीय राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपते हुए विस्तार से सारी चीजें बताई गई कि किस प्रकार विधेयक के प्रभावी होने से राज्य का व्यापार और किसान प्रभावित होंगे। इस विधेयक के माध्यम से शुल्क की वापसी से पुनः अनियमितताएं बढेंगी और पूर्व की दिक्कतें पुनः वापस आ जायेंगी। माननीय राज्यपाल श्री बैश ने प्रतिनिधिमण्डल की सारी बातों को ध्यानपूर्वक सुना।

औद्योगिक विकास हेतु समीक्षात्मक बैठक



झारखण्ड बनने के बाद पहली बार उद्योग विभाग के उच्चाधिकारियों की एक साथ उपस्थिति में ऐतिहासिक बैठक चैंबर भवन में संपन्न हुई। बैठक में उद्योग सचिव, उद्योग निदेशक के अलावा जियाडा के सभी रिजनल डायरेक्टर की उपस्थिति में स्टेकहोल्डर्स के साथ सीधा संवाद किया गया। उद्योग निदेशक श्री जितेंद्र कुमार सिंह ने आश्वस्त किया कि राज्य के उद्यमियों के प्रोत्साहन हेतु उद्योग विभाग द्वारा हर स्तर पर कार्रवाई की जायेगी। औद्योगिक क्षेत्र की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर उन्होंने उद्यमियों की बात को स्वीकार करते हुए कहा कि उद्यमियों के हिसाब से ही योजनाओं को गति दी जायेगी। यह भी कहा कि सब्सिडी के रिम्बर्समेंट में विभाग के साथ ही उद्यमियों द्वारा भी आवेदन देने में विलंब किया जाता है जिस कारण रिम्बर्समेंट में विलंब होता है। उद्योग सचिव श्रीमती वंदना डाडेल ने सभी समस्याओं पर साकारात्मक रूख दिखाते हुए विभाग और स्टेकहोल्डर्स के आपसी समन्वय से समस्याओं के निष्पादन की बात कही। यह भी कहा कि आप सुझाव दें और अपने आइडिया शेयर करें। कहीं भी कोई समस्या हो, दिक्कत आये तो बात करें। सरकार आपके साथ खडी है। लैंड इश्यू पर उन्होंने जल्द ही एक कमिटी बनाकर समीक्षा करने की बात कही। मोर्गेज और लीज अवधि बढाने पर भी उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों की पॉलिसी की समीक्षा कर, उचित सुधार किया जायेगा। बंद पडे खदानों को खोलने, कोल खरीदी में हो रही समस्या और इथनॉल पॉलिसी में आवश्यक संसोधन के सुझाव पर भी उन्होंने खनन विभाग के साथ वार्ता की बात कही। औद्योगिक क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमियों के साथ परामर्श करने और उनका सहयोग लेने की भी बात कही।

केंद्रीय मंत्री के साथ वार्ता



झारखण्ड में सडक परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में विधानसभा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में FJCCI के पदाधिकारियों ने मुख्य रूप से हिस्सा लिया। कार्यक्रम के उपरांत अध्यक्ष श्री किशोर मंत्री के नेतृत्व में प्रतिनिधिमण्डल ने केंद्रीय सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर, झारखण्ड में सडक परियोजनाओं के शिलान्यास के लिए माननीय मंत्री को धन्यवाद दिया। चैंबर अध्यक्ष ने मुलाकात के क्रम में राजमार्गों पर बसों के टोल टैक्स में राहत देने का भी आग्रह किया और कहा कि विभिन्न मार्गों में परिचालित हो रही बसों से प्राप्त की जानेवाली टोल टैक्स की राशि काफी अधिक है, जिसकी समीक्षा आवश्यक है। यह सुझाया गया कि टोल टैक्स गेट में नियमित रूप से पास करनेवाली बसों को दैनिक टोल की राशि में 50 प्रतिशत की छूट एवं मासिक टोल टैक्स का एकसाथ भुगतान करने पर 70 प्रतिशत की छूट देने पर विचार किया जाय।

माननीय राज्यपाल के साथ शिष्टाचार भेंट



फेडरेशन ऑफ झारखण्ड चैंबर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज के पदाधिकारियों ने माननीय राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन से राजभवन में शिष्टाचार मुलाकात की। मुलाकात के क्रम में प्रदेश की आर्थिक प्रगति में व्यापार व उद्योग जगत की भूमिका पर सकारात्मक चर्चा हुई। माननीय राज्यपाल ने राज्य में औद्योगिक विकास और नये निवेश स्थापित करने हेतु झारखण्ड औद्योगिक नीति पर वृहद् चर्चा की। टूरिज्म डेवलपमेंट, शिक्षा, स्वास्थ्य और लॉ एण्ड ऑर्डर के मुद्दे पर भी सकारात्मक वार्ता हुई। प्रतिनिधिमण्डल ने राज्य में अधिकाधिक रोजगार सृजन हेतु विशेषकर लघु उद्योगों के उत्थान के लिए आवश्यक कदम उठाये जाने की बात भी रखी। माननीय राज्यपाल ने झारखण्ड में व्यापारिक व औद्योगिक परिवेश को और अधिक बेहतर बनाने के लिए FJCCI से निरंतर प्रयासरत रहने के लिए कहा।

टंडवा, चतरा जिले का दौरा



राज्यभर के व्यापारियों की FJCCI से दूरी को कम करने के उद्देश्य से वर्तमान सत्र के आरंभ से ही FJCCI द्वारा नियमित रूप से राज्यस्तरीय दौरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में टंडवा और चतरा का दौरा करके अधिकारिक रूप से व्यवसायिक संघ टंडवा को FJCCI से सम्बद्धता दिलाई गई। अध्यक्ष श्री किशोर मंत्री ने व्यवसायिक संघ टंडवा के सभी सदस्यों का उत्साहवर्द्धन करते हुए संगठन विस्तार के लिए प्रेरित किया और जिले के सदस्यों की समस्याओं के समाधान हेतु हरसंभव सहयोग के लिए आश्वस्त किया। उन्होंने झारखण्ड चैंबर द्वारा अप्रैल माह में आयोजित किये जा रहे इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर के आयोजन में भी जिले के व्यापारियों से सहभागिता की अपील की। होल्डिंग टैक्स, भवन नियमितीकरण योजना के साथ ही कृषि शुल्क विधेयक पर किये गये प्रयासों के लिए उपस्थित व्यापारियों ने FJCCI के प्रयासों की सराहना की। साथ ही जीएसटी की जटिलताओं के साथ ही स्थानीय स्तर पर व्यवसायियों के समक्ष हो रही समस्याओं से भी अवगत कराया।

नगर आयुक्त के साथ वार्ता



रांची नगर निगम से जुड़ी समस्याओं पर नगर आयुक्त श्री शशि रंजन से मुलाकात कर ट्रेड लाइसेंस की जटिल प्रक्रियाओं पर चिंता जताते हुए इसके सरलीकरण का आग्रह किया गया। प्रतिनिधिमण्डल द्वारा बाजार टांड में आवंटित दुकानों के किराया विवाद के समाधान पर भी वृहद् चर्चा की गई और इस विवादित मामले के स्थाई समाधान हेतु निगम द्वारा किराया समाधान के रूप में लोकप्रिय योजना लाकर दुकानों को रेगुलराइज किये जाने का आग्रह किया गया जिसपर नगर आयुक्त ने कार्रवाई के लिए आश्वस्त किया। नगर आयुक्त ने अवगत कराया कि ट्रेड लाइसेंस की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जा रहा है। निगम द्वारा इस प्रक्रिया के सरलीकरण की दिशा में की जा रही कार्रवाई की विधिवत् जानकारी से व्यापारियों को अवगत कराने हेतु अध्यक्ष श्री किशोर मंत्री ने पत्र के माध्यम से इसकी जानकारी मांगी जिसपर नगर आयुक्त ने स्वीकार करते हुए इसकी लिखित जानकारी चैंबर को प्रेषित करने के लिए आश्वस्त किया। बकरी बाजार में अस्थाई तर्ज पर पेड पार्किंग की सुविधा विकसित करने के चैंबर के आग्रह पर उन्होंने अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक सकारात्मक कार्रवाई के लिए आश्वस्त किया। बहुबाजार चौक स्थित निगम की दुकानों को ब्रिज निर्माण के लिए खाली करने के दिये गये नोटिसों पर भी वार्ता की गई और दुकानदारों को किसी उचित स्थल पर पुर्नस्थापित करने के उपरांत ही दुकान खाली करने की प्रक्रिया शुरू करने का आग्रह किया गया। नगर आयुक्त ने उदारता दिखाते हुए वहां की दवा दुकानों को वहां आधा जगह देने और मिठाई की दुकानों के लिए अन्य जगह पर वैकल्पिक व्यवस्था देने के लिए आश्वस्त किया।

भवन नियमितीकरण योजना पर विभागीय सचिव संग वार्ता



अनाधिकृत निर्माण को नियमितीकरण करने की योजना के प्रारूप पर दिसंबर माह में दिये गये सुझावों के अतिरिक्त इस योजना में कुछ अन्य सुझावों को समाहित करने के लिए FJCCI की एक बैठक नगर विकास विभाग के सचिव श्री विनय चौबे के साथ मुख्यमंत्री सचिवालय में संपन्न हुई। वार्ता के क्रम में सुझाया गया कि वैसे भवन जिनकी उंचाई 15 मीटर से 21 मीटर तक है, उन्हें भी अतिरिक्त अधिभार लेकर नियमितीकरण करने का प्रावधान किया जाय और प्लिंथ एरिया को 500 स्कवॉयर मीटर से 600 स्कवॉयर मीटर कर दिया जाय। साथ ही वैसे भवन जिनकी उंचाई 15 मीटर से कम है तथा प्लिंथ एरिया 500 स्कवॉयर मीटर से अधिक है और जो नगर निगम क्षेत्र के बाहर हैं, उनमें 500 स्कॅवायर मीटर की बाध्यता को पूर्णरूप से खत्म करना हितकर होगा। यह भी कहा गया कि इस योजना का प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों (जिला परिषदों तथा औद्योगिक क्षेत्रों (जियाडा के क्षेत्र) में भी लागू किया जाय ताकि राज्य का कोई भी हिस्सा इससे अछूता न रहे और पूरा राज्य इस जनकल्याणकारी योजना का लाभ उठा सके। वार्ता के क्रम में योजना को लैंड यूज, रोड विड्थ और बाई लॉज के अन्य प्रावधानों से मुक्त रखने का आग्रह भी किया गया। वार्ता के क्रम में ट्रेड लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया के सरलीकरण पर भी चर्चा की गई। यह सुझाया गया कि निर्धारित शुल्क के साथ एक साधारण आवेदन, जीएसटी निबंधन, आधार, पैन कार्ड लेकर ट्रेड लाइसेंस निर्गत करने की व्यवस्था की जाय। चैंबर अध्यक्ष ने बाजार टांड में निगम द्वारा आवंटित दुकानों के किराया विवाद का समाधान करने का अनुरोध किया। यह आग्रह किया कि वर्षों से चले आ रहे इस विवादित मामले के स्थाई समाधान हेतु निगम द्वारा किराया समाधान के रूप में लोकप्रिय योजना लाकर दुकानों को रेगुलराइज किया जाय। विभागीय सचिव ने सभी मुद्दों पर सकारात्मक रूख दिखाते हुए उचित कार्रवाई के लिए आश्वस्त किया।

'एस्पायर फॉर हर' की लांचिंग



FJCCI और जेन वाई कंसल्टेंसी के सहयोग से चैंबर भवन में एस्पायर फॉर हर संस्थान को झारखण्ड में लांच किया गया। मौके पर एस्पायर फॉर हर की संस्थापक और सीईओ श्रीमती मधुरा दासगुप्ता ने बताया कि कैसे यह संस्थान देश में महिला सशक्तीकरण को आगे लेकर जायेगा। विदित हो कि इस संस्थान का लक्ष्य देश के कार्यबल में 1 मिलियन महिलाओं को जोडना और उनका सशक्तीकरण करना है। अमेजन, गूगल, विप्रो, इंफोसिस, बारक्ले आदि संगठनों के साथ यह संस्थान कार्यरत है। चैंबर अध्यक्ष श्री किशोर मंत्री ने महिला उद्यमियों को MSME से जुडकर व्यवसाय के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। कॉरपोरेट जगत में उभरती उद्यमी सह जेन-वाई कंसल्टेंसी की संस्थापक सुश्री आभा बागरॉय ने भी महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एस्पॉयर द्वारा किये जा रहे प्रयास और भविष्य की योजनाओं पर बात रखी।

रांची रेलमंडल - DRUCC की बैठक



रांची रेल मंडल द्वारा गठित DRUCC की बैठक डीआरएम कार्यालय, हटिया में संपन्न हुई। बैठक में FJCCI के DRUCC प्रतिनिधि श्री नवजोत अलंग ने शामिल होकर रेल सुविधाओं से डीआरएम को अवगत कराया। रियायती यात्री टिकट में मिलनेवाली छूट को पुनः चालू करने के साथ ही कई नई ट्रेनों के परिचालन की मांग की गई। DRUCC प्रतिनिधि ने रांची रेलवे स्टेशन पर IRCTC लाउंज की स्थापना करने, रांची रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 6 को जल्द चालू करने, हटिया स्टेशन पर बडे वातानुकूलित रेस्ट रूम की उपलब्धता करने, रांची रेलवे स्टेशन पर कुली की संख्या बढ़ाने, रांची रेल मंडल से परिचालित होनेवाली ट्रेनों में साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने तथा रेलवे स्टेशन से सिटी बस का परिचालन करने की मांग की गई। मंडल रेल प्रबंधक श्री प्रदीप गुप्ता ने सभी मुद्दों पर उचित कार्रवाई के लिए आश्वस्त किया।



With best compliments from :

MJF LN. SANJAY KUMAR

Lions Club of Daltonganj

DISTRICT CHAIRPERSON
PEACE POSTER CONTEST

Ph. : +91 80029 72970
+91 89868 99719

Shandilya

S Shandilya EXIM Private Limited

TIMBERS EXPORTERS & IMPORTERS

(An ISO 9001 : 2008 Certified Company)





Shandilya Decor Pvt. Ltd.

Deals In : Wholesale Plywood & Laminates

Belwatikar, Daltonganj (Jharkhand)

Website : www.shandilyaexim.com
www.shandilyadecor.com

Reg. Office : 75, Maharshi Devendra Road
(Nimtallah) Kolkata - 700 006, West Bengal, India
Phone : (033) 2272-0054 | Fax : (033) 2272-0034
E-mail : sshandilyaeximpvtltd@gmail.com
Mob. : +91 80029 72970, 89868 99719

चैंबर अध्यक्ष को जयपाल सिंह मुण्डा उद्योग रत्न 2022 का सम्मान



उम्मीद फाउण्डेशन द्वारा भूमिज समाज के अग्रणी मरांग गोमके जयपाल सिंह मुण्डा की 120वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर माननीय वित्तमंत्री डॉ0 रामेश्वर उरांव द्वारा FJCCI के अध्यक्ष श्री किशोर मंत्री को जयपाल सिंह मुण्डा उद्योग रत्न 2022 से सम्मानित किया गया।

टाटा मोटर्स लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक के साथ वार्ता



टाटा मोटर्स लिमिटेड के कॉमर्शियल व्हिकल बिजनेस यूनिट के कार्यकारी निदेशक श्री गिरीश वाघ के रांची प्रवास के दौरान FJCCI के अध्यक्ष श्री किशोर मंत्री ने मुलाकात कर स्थानीय युवाओं को टाटा मोटर्स कंपनी में अधिकाधिक रोजगार सृजन के लिए प्रमुखता से विचार का आग्रह किया। यह भी कहा कि स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के लिए आवश्यक है कि राज्य में कंपनी द्वारा ड्राइविंग प्रशिक्षण और उप चालक प्रशिक्षण सेंटर खोलने की पहल की जाय ताकि यहां के स्थानीय युवा प्रशिक्षण लेकर, यहीं रोजगार प्राप्त कर सकें। चैंबर अध्यक्ष ने कंपनी द्वारा 15-20 एकड़ में एक वर्कशॉप खोलने, पूरे राज्य में गाडियों के मेंटनेंस का दायरा बढ़ाये जाने, पर्यावरण प्रदूषण की बढ़ती समस्या को देखते हुए राज्य सरकार के साथ मिलकर शहर में सीएनजी व इलेक्ट्रिक बसों को चलाने की पहल के लिए भी प्रस्तावित किया जिसपर श्री वाघ ने विचार के लिए आश्वस्त किया।

फिक्की के वार्षिक कन्वेंशन में FJCCI की सहभागिता



नई दिल्ली में 16-17 दिसंबर को फिक्की के आयोजित 95वें वार्षिक कन्वेंशन सह एजीएम में अध्यक्ष श्री किशोर मंत्री के नेतृत्व में FJCCI का आठ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल शामिल हुआ। प्रतिनिधिमण्डल ने फिक्की के एजीएम में विभिन्न राज्यों से आये चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों के साथ मुलाकात की और ईस्टर्न जोन में व्यापारिक विकास को गति देने के मुद्दों पर साथ मिलकर कार्य करने पर चर्चा की। मौके पर प्रतिनिधिमण्डल ने फिक्की के अध्यक्ष श्री संजीव मेहता से भी मुलाकात की और झारखण्ड के स्थानीय मुद्दों पर चर्चा करते हुए, इसमें फिक्की को सहयोगात्मक भूमिका के लिए आग्रह किया। इस एजीएम में माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, सडक राजमार्ग मंत्री श्री नीतिन गडकरी, टाटा संस प्रा0 लि0 के चेयरमेन श्री एन. चंद्रशेखरण ने संबोधित किया।

एक्सपोर्ट प्रमोशन कार्यशाला

एमएसएमई विकास कार्यालय की ओर से एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड जेम पर होटल होलीडे होम में दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में राज्यसभा सांसद श्रीमती महुआ माजी, उद्योग निदेशक और FJCCI अध्यक्ष श्री किशोर मंत्री की विशेष



उपस्थिति रही। सेमिनार में एमएसएमई सेक्टर के विकास और जेम के माध्यम से खरीद-बिक्री को प्रोत्साहित किया गया। यह बताया गया कि जेम पोर्टल पर 40 लाख से अधिक एमएसएमई उद्यमी जुडे हुए हैं। इसमें अब तक करीब 3,57,364 करोड का ट्रांजेक्शन किया गया है। राज्य में सरकारी विभागों में होनेवाली कुल खरीद का 20 फीसदी इस क्षेत्र से करना अनिवार्य किया गया है।

राज्य में औद्योगिक विकास औ
नए निवेश स्थापित करने पर जो
राज्यपाल से मिला चैंबर का प्रतिनिधिमंडल



ट्रेनों को रद्द न कर वैकल्पिक व्यवस्था करे रेलवे : चैंबर
रेल मंत्री को लिखा

28 अप्रैल से इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर

सभी जिलों में पुलिस-व्यापारी समन्व समिति की नियमित बैठक हो : चैंब



ट्रांसपोर्ट से संबंधित दिक्कतों पर चिंता

नाबालिग का स्कूल के समय पर दुकान में न बैठायें : उप श्रमायुक्त



चैंबर भवन में आयोजित कार्यशाला में उपस्थित लोग.

रांची. चैंबर भवन में बुधवार को बाल कानून पर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन हुआ. उप श्रमायुक्त प्रदीप लकड़ा ने शहर के व्यवसायियों को विभिन्न नीतियों की जानकारी देने के साथ श्रम कानूनों का पालन करने की अपील की. साथ ही प्रतिष्ठान में काम कर रहे बच्चों की सुरक्षा को लेकर सेफ्टी ऑडिट कराने का निर्देश दिया. कहा कि पारम्परिक अपने प्रतिष्ठान में 'हमारे यहां बाल श्रमिक कार्यरत नहीं हैं' का पोस्टर लगाना अनिवार्य है. इसके अलावा कार्यस्थल पर महिला-पुरुष को समान काम के बदले समान वेतन देने को अनिवार्य रूप से पालन करने का परामर्श दिया. संस्थान में 20 या इससे अधिक कर्मचारी के कार्यरत होने पर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का प्रावधान लागू करने की सलाह दी. अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए कर्मचारियों के वेतन का भुगतान डिजिटल माध्यम से करने, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, 10 या इससे अधिक कर्मचारी कार्यरत होने पर कार्यस्थल पर शिकायत निवारण समिति का गठन करने, महिला-पुरुष को समान वेतन देने, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने, कार्यस्थल पर पर्याप्त शौचालय, पीने के पानी की व्यवस्था करने, कार्यस्थल पर प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था करने, कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था करने, कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए क्रेच



महिलाओं को व्यापार के लिए किया जाएगा प्रोत्साहित : आस्था

परिवहन सचिव से मिला चैंबर का प्रतिनिधिमंडल

पथ कर से संबंधित निर्देश छह माह तक शिथिल करें : चैंबर

बैठक

वाहनों को गुड्स श्रेणी में डाल परमिट लेने का दबाव

नॉन आरसीसी भवनों पर सेस को घटाकर 5 रु. कि

गलत नीतियों से हो रहा करोड़ों का नुकसान

5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर पर ई-इन्वॉयसिंग अनिवार्य से होगी कठिनाई : चैंबर अध्यक्ष

एमएसएमइ के क्षेत्र में अपार संभावनाएं : चैंबर

व्यापारियों को मिले बीमा स्वास्थ्य और पेंशन सुविधा

आईटी क्षेत्र से रोजगार बढ़ेंगे: चैंबर

रेलवे से जोनल मुख्यालय झारखंड में स्थापित करने की मांग

जिलों में चैंबर आफ कामर्स की होगी स्थापना

औद्योगिक क्षेत्रों में अप्रोच रोड तक की सुविधा नहीं

औद्योगिक क्षेत्रों में सफाई दुरुस्त नहीं : चैंबर

नियमितीकरण योजना पर सुझाव भेंजा गया



अनाधिकृत निर्माण को नियमितीकरण करने के लिए योजना 2022 के प्रारूप पर FJCCI के नेतृत्व में क्रेडाई, बिल्डर एसोसियेशन, आर्किटेक्ट एसोसियेशन के साथ ही विभिन्न व्यापारिक संगठनों की संयुक्त बैठक की गई। बैठक के दौरान यह सुझाव आया कि इस योजना के प्रारूप में दिनांक 31 दिसंबर 2019 के पूर्व निर्मित भवनों के लिए ही नियमितीकरण का प्रावधान किया गया है। लोगों को अनावश्यक कठिनाई नहीं हो इसलिए जरूरी है कि इस अधिसूचना को जारी किये गये दिन से पहले के सभी निर्माण पर लागू किया जाना चाहिए। योजना के प्रारूप पर आमंत्रित किये गये सुझाव की अंतिम तिथि को देखते हुए FJCCI द्वारा सदस्यों की ओर से प्राप्त सभी सुझावों पर विचारोंपरांत सुझावों का संकलन कर, नगर निवेशक को अपना सुझाव प्रेषित किया गया। यह सुझाया गया है कि इस योजना को लैंड यूज के प्रावधानों से मुक्त रखा जाना चाहिए। वैसे भवन जिनकी उंचाई 15 मीटर से अधिक एवं 500 वर्गमीटर प्लिंथ एरिया से ज्यादा है, उनका भी शुल्क के आधार पर नियमितीकरण करने का प्रावधान किया जाना चाहिए। इसी प्रकार इसका प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों (जिला परिषदों तथा औद्योगिक क्षेत्रों (जियाडा के क्षेत्रों) में भी लागू किया जाय ताकि राज्य का कोई भी हिस्सा इससे अछूता न रहे और पूरा राज्य इस जनकल्याणकारी योजना का लाभ उठा सके।

पावरकट के मुद्दे पर उर्जा सचिव के साथ वार्ता



राजधानी रांची समेत कई अन्य जिलों में जारी पावरकट की समस्या से हो रही परेशानियों के निराकरण हेतु FJCCI की बैठक उर्जा सचिव श्री अविनाश कुमार के साथ हुई। बिजली की वर्तमान स्थिति पर आपत्ति जताई गई और कहा गया कि पावरकट का शेड्यूल बनाकर स्टेकहोल्डर्स और नागरिकों के बीच साझा किया जाय। इस क्रम में चैंबर द्वारा राज्य के अलग-अलग औद्योगिक क्षेत्रों के औद्योगिक लोड की जानकारी दी गई। यह दिखाया गया कि औद्योगिक लोड बहुत कम है जिसे सुचारू रूप से चला पाना मुश्किल काम नहीं है। यह भी कहा गया कि सरकारी उपक्रमों पर जेबीवीएनएल का जितना पैसा बकाया है, उसे त्वरित कार्रवाई करते हुए वसूल किया जाय। यह भी सुझाया गया कि कम से कम राज्य के बड़े शहरों में बिजली वितरण की जिम्मेवारी प्रोफशनल प्लेयर को हैंडओवर किया जाय। क्योंकि जैसा कि हम वर्षों से कह रहे हैं कि क्वालिटी और क्वांटिटी बिजली दे पाना JBVNL के बस की बात नहीं है। उर्जा सचिव ने हमारी सभी बातों पर सहमति जताई और अवगत कराया कि कुछ सेलेक्टिव बेसिस पर बिजली वितरण में प्रोफेशनल्स को लाने की कार्रवाई तीव्र गति से की जा रही है। उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि बिजली का एक शेडयूल बनाकर FJCCI के साथ ही आम नागरिकों के बीच साझा किया जायेगा।

नगर निगम



अपर बाजार की यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के साथ ही बाजार टांड स्थित दुकानों के किराया विवाद के स्थाई समाधान हेतु दिसंबर माह में FJCCI द्वारा नगर आयुक्त से मुलाकात की गई। बकरी बाजार में अस्थाई तर्ज पर पेड पार्किंग की सुविधा विकसित करने के चैंबर के आग्रह पर नगर आयुक्त ने सहमति जताते हुए कहा कि वहां क्षतिग्रस्त पडे हुए 200 वाहनों को जनवरी माह में नीलामी कर हटा दिया जायेगा, इसकी सभी प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली गई हैं। बाजार टांड के मामले में यह सुझाया गया कि 100 रू0 स्कवॉयर फीट लेकर दुकानों को रेगुलराइज किया जाय और ब्याज के प्रावधान को समाप्त किया जाय। नगर आयुक्त ने कहा कि किराया जमा करने की व्यवस्था को ऑनलाइन कर, इस समस्या का भी समाधान किया जायेगा। उन्होंने ट्रेड लाइसेंस के सरलीकरण के साथ ही रांची व हटिया रेलवे स्टेशन से सिटी बसों का संचालन प्रारंभ कराने की बात कही।

मीडिएशन सेंटर की शुरूआत



व्यापारी बंधुओं के व्यापारिक विवाद के समाधान हेतु चैंबर भवन में मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया गया। मौके पर झालसा के सचिव सह प्रधान जिला न्यायाधीश श्री संतोष कुमार, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ के प्रोफेशर डॉ0 केशव राव वुर्रकुला, झारखण्ड के पूर्व महाधिवक्ता श्री अजीत कुमार और उच्च न्यायालय के वरीय अधिवक्ता श्री राजीव कुमार उपस्थित थे।

कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड विजेताओं को FJCCI का सम्मान



कॉमनवेल्थ गेम्स में देश को गोल्ड मेडल दिलाने में भारतीय महिला टीम में शामिल झारखण्ड की दो बेटियों लवली चौबे और रूपा रानी तिर्की के महत्वपूर्ण योगदान के लिए FJCCI द्वारा सम्मानित किया गया। मौके पर उपस्थित राज्यसभा सांसद श्रीमती महुआ माजी ने दोनों खिलाडियों को सम्मानित करते हुए कहा कि हम आपसे गौरवान्वित हैं। जरूरतमंद खिलाडियों को सुविधा मुहैया कराई जा सके, इस हेतु उन्होंने FJCCI से भी सरकार की योजना का अधिकाधिक प्रचार करने की बात कही। चैंबर अध्यक्ष श्री किशोर मंत्री ने दोनों खिलाडियों का उत्साहवर्द्धन करते हुए झारखण्ड में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए चैंबर के स्पोर्ट्स कमिटी में भी खिलाडियों को शामिल होने की अपील की और कहा कि FJCCI द्वारा भी खिलाडियों के प्रोत्साहन हेतु सहयोग किया जायेगा। गोल्ड विजेता लवली चौबे और रूपा रानी तिर्की ने उनके सम्मान में आयोजित कार्यक्रम के लिए FJCCI के प्रति आभार जताया और कहा कि देश के लिए खेलना और गोल्ड लाना उनकी जिंदगी का रोचक इतिहास बन गया है।

नागरिकों का सम्मान



बड़ा तालाब में दुर्घटनाग्रस्त वाहन में फंसे परिवार की जान बचानेवाले चार युवाओं (मो0 मोहसीन, मो. साजीद, मो. कलाम, मो. अरमान) को चैंबर भवन में आमंत्रित कर FJCCI द्वारा सम्मानित करते हुए उनका प्रोत्साहन किया गया। चैंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने चारों युवाओं के इस प्रयास की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस प्रयास से मानवता की मिशाल प्रस्तुत हुई है। साथ ही उन्होंने चारों युवाओं को चैंबर की ओर से जरूरत पड़ने पर हरसंभव सहयोग के लिए भी आश्वस्त किया।

विद्यार्थियों का प्रोत्साहन



परीक्षा पे चर्चा से पूर्व गुरूनानक स्कूल में आयोजित आर्ट एंड पेंटिंग प्रतियोगिता में शामिल विभिन्न स्कूल के बच्चों को प्रोत्साहित करने हेतु FJCCI पदाधिकारियों ने शामिल होकर उनका उत्साहवर्द्धन किया। एक्जाम वॉरियर्स के रूप में शामिल सभी बच्चों ने अपनी प्रतिभा और कौशल का अद्भुत प्रदर्शन किया।

बस ट्रांसपोर्ट

दक्षिणी छोटानागपुर क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार की दिनांक 27 दिसंबर को आयोजित होनेवाली बैठक में बस व्यवसायियों की समस्याओं पर प्रमुखता से चर्चा हो सके इस हेतु दिनांक 15 दिसंबर को चैंबर भवन में बस ऑनर एसोसियेशन रांची के सदस्यों ने चैंबर अध्यक्ष के साथ वार्ता की। बैठक में लिये गये निर्णयों के आलोक में FJCCI

द्वारा प्राधिकार के सचिव को पत्र प्रेषित कर ट्रांसपोर्ट रिवीजन केस संख्या 25/13 के आदेश को संज्ञान में रखते हुए समय-सारणी अंतराल के संबंध में दो बड़ी बसों के बीच का अंतराल 10 मिनट और 2 छोटी बसों के बीच में 5 मिनट का अंतराल रखने का सुझाव दिया गया। इसी प्रकार वैसे आवेदन जिनका रूट फॉर्मूलेशन नहीं हुआ है, उन्हें अस्वीकृत करते हुए वैसे आवेदन को रद्द करने, जिस मार्ग पर आवेदन नहीं करने का अनुरोध किया गया है, उसे भी तुरंत प्रकाशन से हटाकर अस्वीकृत करने और प्राधिकार की बैठक के आयोजन से पूर्व FJCCI के साथ एक बैठक करके पारदर्शिता के साथ समय सारणी निर्गत करने की पॉलिसी बनाये जाने एवं FJCCI के 2 सदस्यों को बैठक में स्थाई रूप से हिस्सा लेने की अनुमति देने की बात कही गई है।

ट्रॉफिक एसपी के साथ वार्ता



राजधानी रांची में जाम की समस्या से लोगों की बढती परेशानी और इसके निराकरण हेतु चैंबर भवन में एक बैठक संपन्न हुई जिसमें पुलिस अधीक्षक श्री नौशाद आलम ने व्यापारियों से अपील करते हुए कहा कि व्यापारी अपनी दुकानों के सामान सड़कों पर ना रखें और सडकों को अतिक्रमण मुक्त रखने में प्रशासन का सहयोग करें। साथ ही उन्होंने व्हाईट लाईन का सख्ती से पालन करने की भी अपील की। यह भी कहा कि शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाये रखने के लिए जरूरी है कि अपने दुकान की सीमा से बाहर व्यवसायिक गतिविधि ना करें। वार्ता के क्रम में उन्होंने जाम की समस्या से निपटने के लिए किये जा रहे प्रयासों की भी जानकारी दी और अवगत कराया कि गलत तरीके से पार्क किये गये वाहनों पर सख्ती बरतने और उन्हें उसी स्थल पर लॉक करने के लिए कई ट्रॉफिक उपकरण भी खरीदे जा रहे हैं। यातायात के लिए ड्रोन कैमरा भी मंगाया गया है जिसके माध्यम से शहर की जाम की समस्या की रियल टाईम मॉनिटरिंग की जायेगी। चौक चौराहों पर ट्रॉफिक सिग्नल और सीसीटीवी कैमरे को भी दुरूस्त किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक के आग्रह पर चैंबर अध्यक्ष ने यह आश्वस्त किया कि सीएनजी फिल करनेवाली एजेंसी को रांची में स्थापित कराने में फेडरेशन आवश्यक सहयोग करेगा। उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि शहर की यातायात व्यवस्था पर एक सप्ताह के अंदर शहर की विभिन्न संस्थाओं के साथ चैंबर भवन में पुनः एक बैठक आहूत की जायेगी।

IIT टॉक शो



राज्य में शिक्षा के बढते अवसर पर दिनांक 15 जनवरी को FJCCI द्वारा चैंबर भवन में पूर्व आईएएस एवं आईआईटीयन श्री केके खंडेलवाल का टॉक-शो कराया गया। उन्होंने उपस्थित बच्चों का मार्गदर्शन किया। टॉक शो में शामिल बच्चों ने आईआईटी की तैयारी कब से करें, कितने देर पढें इत्यादि प्रश्न भी पूछे जिसका श्री खंडेलवाल ने संतोषप्रद जवाब दिया। एजुकेशन उप समिति के चेयरमैन श्री विकास सिन्हा के प्रयास से टॉक शो में उपस्थित विद्यार्थी लाभान्वित हुए।

चैंबर पत्रिका



FJCCI के वर्तमान सत्र की पत्रिका के प्रथम अंक का विमोचन पद्मश्री श्री अशोक भगत द्वारा किया गया। पत्रिका का विमोचन करते हुए उन्होंने राज्य के आर्थिक विकास के साथ ही सामाजिक उत्थान की दिशा में FJCCI द्वारा किये जा रहे प्रयासों की सराहना की। चैंबर में सभी वर्ग के लोगों का योगदान बढ़े, इस दिशा में वर्तमान में किये जा रहे प्रयासों की भी उन्होंने प्रशंसा की और इस प्रयास को और अधिक गति देने के लिए प्रेरित किया। साथ ही चैंबर को और अधिक सशक्त बनाने के लिए उन्होंने झारखण्ड चैंबर ऑफ कॉमर्स का सत्र दो वर्षों का करने की भी सलाह दी। मौके पर महेश्वरी सभा के झारखण्ड-बिहार के पूर्व अध्यक्ष श्री पवन मंत्री, प्रबुद्धजन श्री अयोध्यानाथ मिश्र, श्री अनिल ठाकुर ने भी चैंबर को मजबूती देने के लिए चैंबर अध्यक्ष द्वारा किये जा रहे प्रयासों की सराहना की और पत्रिका के प्रकाशन कार्य को प्रशंसनीय बताया।

रांची में डीवीसी के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस खुलने का चैंबर ने स्वागत किया

राजधानी रांची के अशोक नगर में डीवीसी के नये डिस्ट्रीब्यूशन कार्यालय खुलने के अवसर पर FJCCI के पदाधिकारी विशेष रूप से शामिल हुए। इस दौरान डीवीसी के उच्चाधिकारियों और FJCCI पदाधिकारियों की बैठक भी हुई। उच्चाधिकारियों द्वारा यह बताया गया कि डीवीसी कमांड एरिया में डीवीसी द्वारा तकरीबन 25 नये सब स्टेशन बैठाये जा रहे हैं जिससे 11 केवीए के उपभोक्ताओं



को लाइन दिया जायेगा। चैंबर अध्यक्ष श्री किशोर मंत्री और एनर्जी उप समिति के चेयरमेन श्री बिनोद तुलस्यान ने संयुक्त रूप से इस प्रयास की प्रशंसा करते हुए कहा कि सब स्टेशनों से 11 केवीए के उपभोक्ताओं को लाइन दिये जाने से कमांड एरिया के मझौले कंज्यूमर को काफी सुविधा होगी। यह भी कहा गया कि आनेवाला समय बिजली का ही है। स्कूटर से लेकर इलेक्ट्रिक बसों का ही चलंत मार्केट में हैं। ऐसे में डीवीसी द्वारा ग्राउण्ड स्तर तक इसका लाभ उपभोक्ताओं को दिया जाना सुनिश्चित करना चाहिए। चैंबर उपाध्यक्ष श्री आदित्य मल्होत्रा ने डीवीसी कमांड एरिया में बिजली कटौती से हो रही परेशानियों पर भी चर्चा करते हुए, इसमें सुधार का आग्रह किया।

बजट पूर्व गोष्ठी में FJCCI के सुझाव



झारखण्ड बजट में स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के साथ ही सरकार के राजस्व संग्रह में वृद्धि हेतु FJCCI ने राज्य सरकार द्वारा आयोजित बजट पूर्व गोष्ठी में शामिल होकर अपने कई सुझावों से अवगत कराया। चैंबर अध्यक्ष श्री किशोर मंत्री ने माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बजट के लिए सुझाव आमंत्रित किये जाने की प्रक्रिया का स्वागत करते हुए सरकार के राजस्व संग्रह में वृद्धि हेतु उन्होंने राज्य में बंद पडे लौह अयस्क की खदानों को जल्द खोलने, खदान से निकले आयरन-ओर, बॉक्साइट इत्यादि के ऑक्शन, मिनरल्स की आसान उपलब्धता के लिए सुविधाजनक नीति का निर्माण करने, बिना नक्शे के बने भवनों को नियमितीकरण करने, वर्तमान उत्पाद नीति में संशोधन करते हुए ओडिसा अथवा कर्नाटक सरकार की नीति का अनुसरण करने, खासमहल भूमि को फ्रीहोल्ड करने की प्रक्रिया का सरलीकरण करने और व्यवसायिक वाहनों पर वर्षों से बकाया टैक्स की प्राप्ति हेतु वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाने का सुझाव दिया। यह कहा कि इन उपायों से सरकार को हजारों करोड रू0 की तत्काल आमदनी होगी। चैंबर अध्यक्ष ने वनोत्पाद का राज्य में ही वैल्यू एडेड करते हुए संयंत्र स्थापित कराने, जिलेवार ट्राइबल बिजनेस डेवलपमेंट का गठन करने, प्रत्येक जिले में एक औद्योगिक क्षेत्र की अनिवार्यता के साथ केवल एमएसएमई मैनुफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 50-100 एकड अतिरिक्त लैंड बैंक विकसित करने, राज्य में व्यापार-उद्योग आयोग का गठन करने, राज्य के पांचों प्रमण्डल में ट्रेड बिजनेस सेंटर की स्थापना करने, सभी जिलों में ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण, बस स्टैंड का आधुनिकीकरण करने, पांचों प्रमण्डल में ड्राइविंग प्रशिक्षण और उप चालक प्रशिक्षण सेंटर खोलने, राज्य में उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थान और उच्च कोटि के अस्पताल व रिसर्च सेंटर की स्थापना करने और खेलगांव को स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के रूप में तब्दील करने के साथ ही FJCCI को स्टेट इंडस्ट्री पार्टनर नियुक्त करने का सुझाव शामिल है।

रामगढ़ में FJCCI के कार्यकारिणी समिति की बैठक

FJCCI के वर्तमान सत्र के कार्यकारिणी समिति की बैठक रामगढ़ जिमखाना क्लब में संपन्न हुई। बैठक में रामगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों के अलावा रामगढ़ व हजारीबाग के FJCCI के डायरेक्ट सदस्य भी शामिल हुए। कई वर्षों के बाद फेडरेशन की



कार्यकारिणी बैठक रामगढ़ में आयोजित किये जाने पर रामगढ़ के सदस्यों ने वर्तमान पदाधिकारियों के प्रयास की प्रशंसा की और कहा कि फेडरेशन को राज्य के प्रत्येक जिले में एक बैठक अवश्य सुनिश्चित करनी चाहिए। चैंबर अध्यक्ष ने फेडरेशन को मजबूती देने के लिए जिले से अधिकाधिक संख्या में सदस्यता लेने की भी अपील की। बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा कहा गया कि रामगढ जिले में लघु खनिज, बालू, मेटल, बोल्डर के अभाव के कारण विकास कार्य, व्यवसायिक भवन, निजी भवन आदि का निर्माण लगभग ठप पडा हुआ है। बालू की कमी से बालू की कीमतों में वृद्धि के साथ ही सरकार को राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। खनन पटटा लीज

हेतु खनन क्षेत्र की नीलामी, पॉल्यूशन बोर्ड से एनओसी फिर लीज एकरारनामा इन सब कार्रवाई में भी समय सीमा का कोई निर्धारण नहीं है, रॉयल्टी में वृद्धि से भी बालू व पत्थर काफी महंगे होते जा रहे है, जिसकी सरकार को समीक्षा करनी चाहिए। रामगढ चैंबर के अध्यक्ष श्री पंकज तिवारी ने रामगढ जिले में इंडस्ट्रीयल पार्क के निर्माण को आवश्यक बताते हुए रामगढ छावनी क्षेत्र की बढ़ती आबादी एवं घटते भूमि के मद्देनजर छावनी परिषद में वर्षों से लागू भवन उपनियम में संशोधन की आवश्यकता बताई। चैंबर अध्यक्ष ने सभी मुद्दों पर विभागीय वार्ता के लिए आश्वस्त किया।

फॉरेस्ट एण्ड टिम्बर



काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना एवं विनियमन हेतु राज्य सरकार द्वारा गठित राज्यस्तरीय समिति की प्रधान मुख्य वन सरंक्षक व एचओएफएफ की अध्यक्षता में दिनांक 25.11.2021 को संपन्न हुई बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुपालन में हो रहे विलंब पर सदस्यों द्वारा चर्चा की गई। चिंतनीय है कि अब तक राज्य सरकार द्वारा इसकी अनुशंसा नहीं भेंजी गई है जिस कारण प्रदेश में आरा मिलों का व्यापार बंद पडा है। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने राज्य सरकार से इस मामले में त्वरित संज्ञान लेने का अनुरोध किया।

पर्यटन निदेशक के साथ वार्ता



दिसंबर माह में FJCCI प्रतिनिधिमण्डल ने पर्यटन निदेशक श्रीमती अंजली यादव और महाप्रबंधक श्री आलोक कुमार के साथ मुलाकात कर राज्य के पर्यटन विकास के मुद्दों पर वार्ता की।

कैरियर कॉउंसलिंग

नेहरू युवा केंद्र द्वारा डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में कैरियर कॉउंसलिंग का आयाजन किया गया। विदित हो कि युवा एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से युवाओं को कौशल विकास, स्वरोजगार एवं विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्यक्रम संचालित किये जा



रहे हैं। इस अवसर पर चैंबर अध्यक्ष श्री किशोर मंत्री ने बतौर मुख्य अतिथि शामिल होकर, युवाओं का मार्गदर्शन किया और युवाओं को उद्यमिशीलता के गुण सिखाये।

ZRUCC, Eastern Railway में FJCCI के प्रतिनिधि का मनोनयन



ZRUCC, Eastern Railway में श्री प्रदीप अग्रवाल, गिरिडीह को फेडरेशन ऑफ झारखण्ड चैंबर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज (FJCCI) का प्रतिनिधि मनोनित किया गया है। ZRUCC, Eastern Railway का यह सत्र 01.02.2023 से 31.01.2025 तक प्रभावी रहेगा। सदस्यों से आग्रह है कि रेलवे की बेहतरी के साथ ही यात्री सुविधा से संबंधित अपने सुझाव नियमित रूप से हमें प्रेषित करें।

डीजीपी संग वार्ता



लॉ एंड ऑर्डर की समस्याओं पर वार्ता हेतु FJCCI की बैठक डीजीपी श्री अजय कुमार सिंह के साथ हुई। प्रतिनिधिमण्डल द्वारा राज्य की विधि व्यवस्था में गुणात्मक सुधार के लिए कई सुझाव भी दिये गये। एसपी के नेतृत्व में सभी जिलों में चैंबर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से पुलिस-व्यापारी समन्वय समिति की बैठक आयोजित करने के साथ ही रांची नगर निगम के इनफोर्समेंट कर्मियों द्वारा खाकी वर्दी के उपयोग से लोगों के बीच बन रही भ्रम की स्थिति पर भी प्रतिनिधिमण्डल ने चिंता जताई। गिरिडीह में चार वर्षों से आरंभ किये गये ट्रॉफिक

थाना में अब तक प्रशिक्षित ट्रॉफिक पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति नहीं होने से हो रही समस्याओं से भी अवगत कराया गया। दुर्घटनाग्रस्त व्यवसायिक वाहनों की जांच में थाना स्तर पर होनेवाले विलंब पर भी चर्चा की गई। कहा गया कि छोटी-छोटी दुर्घटनाओं में व्यवसायिक वाहनों को जब्त करके वाहन के जमानत के लिए वाहन मालिकों को न्यायालय की शरण में जाने के लिए बाध्य किया जाता है। जिस कारण महीनों समय लग जाता है जिसमें वाहन का परमिट, फिटनेस, टैक्स, इंश्योरेंश का भारी नुकसान होता है और जनहित में आवागमन बाधित हो जाता है। जबकि झारखण्ड मोटरवाहन अधिनियम के रूल्स 215 के अनुसार राज्य के व्यवसायिक वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने पर संबंधित थाना द्वारा उन्हें पीआर बांड लेकर तुरंत छोड़ा जाना चाहिए ताकि व्यवसायिक वाहनों का व्यापार प्रभावित न हो। बैठक के दौरान टाइगर मोबाइल को और अधिक सशक्त बनाने पर जोर देते हुए प्रतिनिधिमण्डल ने राज्यस्तर पर सभी जिलों में पुनः बडे रूप में टाइगर मोबाइल गस्ती सेवा को चालू करने की मांग की। होटल संचालकों की दैनिक रिपोर्ट थाना में भौतिक रूप से जाकर जमा करने से होनेवाली परेशानियों पर भी चर्चा की गई। यह आग्रह किया गया कि संबंधित थाना द्वारा ईमेल अथवा वॉट्सएप्प से होटल की दैनिक रिपोर्ट लेने की व्यवस्था की जाय। पुलिस महानिदेशक श्री अजय कुमार सिंह ने सभी मुद्दों पर सकारात्मक रूख दिखाते हुए उचित कार्रवाई के लिए आश्वस्त किया।

झारखंड बजट 2023-24 की मुख्य विशेषताएं:

माननीय वित्त मंत्री डॉ0 रामेश्वर उरांव द्वारा वित्तिय वर्ष 2023-24 के लिए 1 लाख 16 हजार 4 सौ 18 करोड रू0 का सकल बजट प्रस्तुत किया गया। माननीय वित्त मंत्री ने अवगत कराया कि वर्ष 2020-21 से राज्य सरकार द्वारा सिंकिंग फंड में लगातार निवेश किया जा रहा है। इस उद्देश्य से अब तक इसमें लगभग 1004 करोड रू0 का निवेश किया गया है, जिसका उपयोग केवल ऋण भुगतान के लिए ही किया जा रहा है। इससे स्वस्थ आर्थिक हित के साथ साथ राज्य की साख भी बढी है।

1. राज्य में उद्योगों के विकास और विस्तार को प्रधानता देते हुए वर्ष 2023-24 में उद्योग विभाग के लिए 474.50 करोड रू0 का बजट प्रस्तावित है।
2. सरकार ने यह स्वीकार किया कि पुराने औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत संरचना काफी जीण-शीर्ण अवस्था में है, जिसका कुप्रभाव औद्योगिक इकाईयों पर पड रहा है। आगामी वित्तिय वर्ष में सभी पुराने औद्योगिक क्षेत्र के पुनर्निमाण के साथ ही नये औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण प्रस्तावित किया गया।
3. एक डेडिकेटेड एमएसएमई निदेशालय स्थापित किया जायेगा। साथ ही एमएसएमई के प्रोत्साहन हेतु नई एमएसएमई पॉलिसी लागू की जायेगी।
4. झारखण्ड फूड/फीड प्रसंस्करण प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी 2015 के दो वर्षों के विस्तार के उपरांत नई खाद्य प्रसंस्करण नीति गठित करने का प्रस्ताव है।
5. राज्य में पर्यटन को उद्योग का दर्जा देते हुए अलग से पर्यटन नीति का गठन किया जायेगा।
6. नेतरहाट को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने हेतु नेतरहाट टूरिस्ट डेवलपमेंट ऑथोरिटी बनाने का प्रस्ताव है।
7. राज्य सरकार द्वारा आरटीआई पोर्टल विकसित किया जायेगा।
8. स्टेट डाटा रिकवरी सेंटर का निर्माण किया जायेगा।
9. आम जनता के लिए सस्ते दर पर एयर एंबुलेंस सेवा प्रारंभ की जायेगी।
10. रिजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत दुमका तथा बोकारो हवाई अड्डा से उडान प्रारंभ किया जायेगा।
11. रांची मास्टर प्लान, 2037 के अनुरूप इनर रिंग रोड के मिसिंग लिंक के निर्माण का प्रस्ताव है।
12. साहेबगंज, बरहेट, जामताडा, दुमका, गोविंदपुर एडीबी पथ का फोरलेन में उन्नयन प्रस्तावित है।
13. कोडरमा, जमुआ, गिरिडीह, टुण्डी, गोविंदपुर पथ का फोरलेन में उन्नयन प्रस्तावित है।
14. बोकारो, रांची में मेडिकल कॉलेज की स्थापना।
15. चलंत ग्राम क्लीनिक का संचालन एवं प्रबंधन।
16. नये नर्सिंग कॉलेज एवं फॉर्मेसी कॉलेज की स्थापना।
17. सभी राजकीय विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिए इनोवेशन कम स्टार्टअप सेंटर की स्थापना का प्रस्ताव है।
18. गिरिडीह एवं जमशेदपुर में नये डेयरी प्लांट तथा रांची में मिल्क पावडर प्लांट एवं मिल्क प्रोडक्ट प्लांट की स्थापना की जायेगी।
19. राज्य में आधारभूत संरचनाओं का विकास तेजी से करना सरकार की प्राथमिकता में है। इस वित्तिय वर्ष 25,317 करोड रू0 पूंजीगत परिव्यय का आकलन किया गया है।
20. वर्तमान वित्तिय वर्ष में राजस्व व्यय के लिए 84,676 करोड रू0 प्रस्तावित है तथा पूंजीगत व्यय अंतर्गत 31,742 करोड़ रू0 का प्रस्ताव है।
21. बजट में प्रावधानित सकल राशि को यदि प्रक्षेत्र के दृष्टिकोण से देखा जाय तो सामान्य प्रक्षेत्र के लिए 33,378.75 करोड रू0, सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए 43,303.44 करोड़ रू0 तथा आर्थिक प्रक्षेत्र के लिए 39,376.11 करोड़ रू0 उपबंधित किये गये हैं।
22. वित्तिय वर्ष 2023-24 में राज्य के आर्थिक विकास दर वर्ष 2011-12 के कॉस्टेंट प्राइज तथा करेंट प्राइज पर क्रमशः 7.4 प्रतिशत तथा 11.06 प्रतिशत अनुमानित है।
23. कृषि एवं सम्बद्ध प्रक्षेत्र के लिए बजट में 11.84 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए लगभग 4,627 करोड़ रू0 का बजट प्रस्तावित है।

Deepak Sarawgi
Call : +91 94311-70644
+91 9334454770

Akshit Agencies

Distributors :-
• Johnson & Johnson Ltd. • B/Brau Medical (I) Pvt. Ltd. • Boston Scientific (I) Pvt. Ltd.
• Baxter (I) Pvt. Ltd. • Bard (I) Pvt. Ltd. • India Medtronic Pvt. Ltd. • 3M (I) Ltd.
• Sims Portex • Vygon (I) Pvt. Ltd.

Deals in : All Types of Surgical Goods Critical Care Disposables & Medicines

2nd Floor, K.C. Complex, Vishnu Gali, Old Commissioner, Compound, Ranchi-834001
Phone : 0651-2204383 (O) | Email : aaranchi@gmail.com

Sarawagi Futures Pvt. Ltd.

Harsh Sarawagi
Director
+91 62078 99204, +91 95462 23384

-: Head Office :-
Flat No. 102, Rishabh Apartment, Gangaur By Lane, Kutchery Road
Ranchi - 834001 (Jharkhand)

-: Branch Office :-
1st Floor, Building Opposite Kitchen & Locks
SN Ganguly Road, OC Compound
Ranchi - 834001 (Jharkhand)

प्रमण्डलीय गतिबिधियाँ...

पलामू प्रमण्डल

विशेष संकलन

आरा मिल संचालकों की कठिनाई पर पीसीसीएफ के साथ वार्ता



कुंदरी वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा डाल्टनगंज में अवस्थित 12 आरा मिलों को सील करने के मामले में 20 मार्च को क्षेत्रीय उपाध्यक्ष श्री संजय कुमार के नेतृत्व में पलामू चैंबर और पलामू वनोपज लघु उद्योग संघ के पदाधिकारियों ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक से मिलकर, मामले में हस्तक्षेप का आग्रह किया। यह अवगत कराया गया कि पिछले 6 दशक से यह मिलें रेलवे द्वारा आवंटित भूमि पर संचालित हो रही हैं। रेलवे द्वारा किराया बढाये जाने से असंतुष्ट होकर आरा मिल संचालक माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय की शरण में हैं। माननीय न्यायालय द्वारा तीन माह का समय देते हुए रेलवे की भूमि का खाली करने के दिये गये आदेश पर मिल संचालकों ने उचित दस्तावेज के साथ स्थानांतरण के लिए आवेदन दिया है जिसपर कार्रवाई जारी है। इस दौरान संचालकों द्वारा लाइसेंस नवीकरण के लिए भी सभी दस्तावेज एवं शुल्क ससमय जमा कर दिया गया है। किंतु बिना किसी पूर्व सूचना के कुंदरी वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा जनवरी माह में सभी आरा मिलों को सील कर दिया गया और आयात-निर्यात पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है। यह आग्रह किया गया कि वास्तविक कठिनाईयों को देखते हुए आरा मिल संचालकों को एक वर्ष का समय दिया जाय। इस अवधि में रेलवे से पक्ष में कोई निर्देश प्राप्त नहीं की स्थिति में व्यवसायी स्वयं ही अपना मिल अन्यत्र स्थानांतरित करा लेंगे। पीसीसीएफ ने प्रतिनिधिमण्डल की बातों पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए उचित कार्रवाई के लिए आश्वस्त किया।

नार्थ छोटानागपुर प्रमंडल



FJCCI और रामगढ चैंबर ऑफ कॉमर्स के संयुक्त तत्वावधान में रामगढ में एक बैठक आयोजित की गई जिसमें राज्यसभा सांसद श्रीमती महुआ माजी और गिरिडीह विधायक श्री सुदिव्य कुमार शामिल हुए। व्यापारियों ने एकमत से कृषि शुल्क विधेयक को झारखण्ड के व्यापार, किसान और आम उपभोक्ताओं के प्रतिकूल बताया और इसे जनहित में समाप्त करने का आग्रह किया। समस्या को वास्तविक समझते हुए गिरिडीह विधायक श्री सुदिव्य कुमार ने सभा के बीच में ही माननीय मुख्यमंत्री से चैंबर अध्यक्ष की वार्ता कराई। माननीय मुख्यमंत्री ने चैंबर अध्यक्ष को आश्वस्त करते हुए कहा कि व्यापारियों के हितों का ख्याल रखते हुए ही कोई कार्य किया जायेगा। राज्य के आर्थिक विकास में व्यापारियों के योगदान की प्रशंसा करते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने गिरिडीह विधायक के आग्रह पर जल्द ही स्टेकहोल्डर्स की समस्याओं पर चैंबर अध्यक्ष के साथ एक बैठक करने की बात भी कही। व्यापारियों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि कृषि शुल्क को लेकर व्यापारी चिंतित नहीं हों। सरकार ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगी जिससे राज्य के व्यापारी, किसान और उपभोक्ता प्रभावित हों। सभा में उपस्थित राज्यसभा सांसद श्रीमती महुआ माजी और गिरिडीह विधायक श्री सुदिव्य कुमार ने भी कृषि विधेयक को लेकर व्यापारियों की सभी मांगों पर विचार करने के लिए हरसंभव सहयोग के लिए आश्वस्त किया।

कोल्हान प्रमण्डल की गतिविधियाँ...



आयकर अधिनियम में किये गये बदलाव तथा टीडीएस के नये प्रावधानों की जानकारी हेतु एक संगोष्ठी का आयोजन कराया गया। सहायक आयकर अधिकारी श्री बिनोद अग्रवाल के नेतृत्व में उपस्थित उच्चाधिकारियों द्वारा आयकर से संबंधित सभी प्रावधानों की जानकारी दी गई। क्षेत्रीय उपाध्यक्ष श्री नीतिन प्रकाश को आगामी दो वर्षों के लिए SE Railway में ZRUCC का प्रतिनिधि भी मनोनित किया गया है। श्री प्रकाश के नेतृत्व में FJCCI के सदस्यता संख्या में वृद्धि के साथ ही स्टेकहोल्डर्स की कई महत्वपूर्ण समस्याओं पर गतिविधियों का आयोजन किया गया है।


SG
EXOTICA
Luxury Redefined
Opportunity to Buy Luxury 3/4/5 BHK Flats at Competitive Rates in the Tallest & Best SkyScraper in Jharkhand
The Ultimate Choice with Unmatched Facilities :
State of the art Design with Luxury & Privacy.
All Sides Open Spacious Flats with Large Balconies.
A large landscaped Garden with Exclusive Children's Play Area & Walking Track.
Fully Air Conditioned Club House with
All Weather Swimming Pool & Spa
Fully Equipped Modern Gymnasium
Banquet Hall & Multipurpose Party Hall
Home Theatre, Card Room, Squash, Badminton Courts, Table Tennis & Pool Table
Indoor Todlers Play Area, Yoga Room
Fully Furnished Guest House
HURRY!
LIMITED FLATS AVAILABLE
+91 9431114308
S.G. Exotica, 83, Hazaribagh Road, Ranchi - 1

जियाडा के क्षेत्रीय निदेशक के साथ वार्ता



डाल्टनगंज में एक नये औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना को लेकर FJCCI के नेतृत्व में पलामू चैंबर ऑफ कॉमर्स और पलामू वनोपज लघु उद्योग संघ की बैठक जियाडा के क्षेत्रीय निदेशक श्री अजय कुमार सिंह से हुई। यह कहा गया कि पलामू में एक ही औद्योगिक क्षेत्र है जहां पूर्व से ही बड़े-बड़े शोरूम एवं अन्य इकाईयों को भूखंड आवंटित है और वर्तमान में यहां कोई भूखण्ड रिक्त नहीं है जिस कारण डाल्टनगंज में कई औद्योगिक इकाइयां भूमि के अभाव में अपनी इकाई स्थापित करने में असमर्थता महसूस कर रही हैं। इस बात पर भी चिंता जताई गई कि वर्षों से डाल्टनगंज स्थित रेलवे स्टेशन के निकट आवंटित रेलवे भूमि पर आरा मिल एवं लकडी का व्यवसाय संचालित कर रहे SSI और MSME में निबंधित व्यवसायियों को रेलवे द्वारा प्लॉट खाली करने का निर्देश दिया गया है जिससे व्यापारियों का व्यापार बंद होने की स्थिति में हैं। प्रसन्नता है कि FJCCI के सुझाव पर क्षेत्रीय निदेशक द्वारा उपायुक्त, पलामू को 200 से 400 एकड सरकारी भूमि हस्तांतरित करने हेतु पत्र प्रेषित कर दिया गया है।

श्रम कानूनों पर जागरूकता कार्यशाला



श्रम कानूनों पर जागरूकता हेतु श्रम नियोजन विभाग द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के माध्यम से न्यूनतम वेतन, बोनस एक्ट, डिजीटल भुगतान, ग्रेच्युटी एक्ट समेत नियोजकों की सुविधा के लिए विभागीय नीतियों से व्यापारियों को अवगत कराया गया। उप श्रमायुक्त श्री प्रदीप लकडा ने राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम की जानकारी से अवगत कराते हुए नियोजकों को अपने प्रतिष्ठान में 75 फीसदी स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात कही। व्यापारियों की असमंजसता को देखते हुए यह स्पष्ट किया गया कि पूर्व से कार्यरत कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने पर उनके स्थान पर स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देनी है। यानी जिस प्रतिष्ठान-कारखाने में जैसे जैसे कर्मचारी सेवानिवृत्त होंगे, उनके स्थान पर नये लोगों में स्थानीय को रोजगार उपलब्ध कराना होगा। 75 फीसदी पूरा होने पर शेष 25 फीसदी अन्य राज्य के लोगों को रोजगार दे सकते हैं। आरसीसी भवनों की भांति नॉन आरसीसी संरचना/निर्माण पर लग रहे सेस पर पुनर्विचार के लिए भी चैंबर अध्यक्ष ने आग्रह किया। उप श्रमायुक्त ने समस्या की वास्तविकता को स्वीकार करते हुए इसे बोर्ड में चर्चा कराने के लिए आश्वस्त किया। कार्यशाला में उपस्थित व्यवसायियों ने राज्य में कुशल श्रमिकों की पर्याप्त उपलब्धता से भी अवगत कराया जिसपर श्रमाधीक्षक अविनाश कृष्णन ने डिस्ट्रीक्ट स्किल कमिटी के समक्ष इस समस्या को रखने के लिए आश्वस्त किया।

15 YEARS OF EXCELLENCE

PROUD MEMBER OF : BNI Yi Young Indians WE CAN WE WILL



Rahul Mazumdar
Proprietor (Akash Consultancy), MBA
EPF/ESIC Consultant
Yi, (Chairperson Road Safety 2022-23)
Member, Education Sub Committee FJCCI, 2022-23

AKASH Consultancy

A CONSULTING FIRM FOR EPF, ESIC, PT, DSC, LABOUR, RULE, & EMPLOYMENT EXCHANGE RETURN.

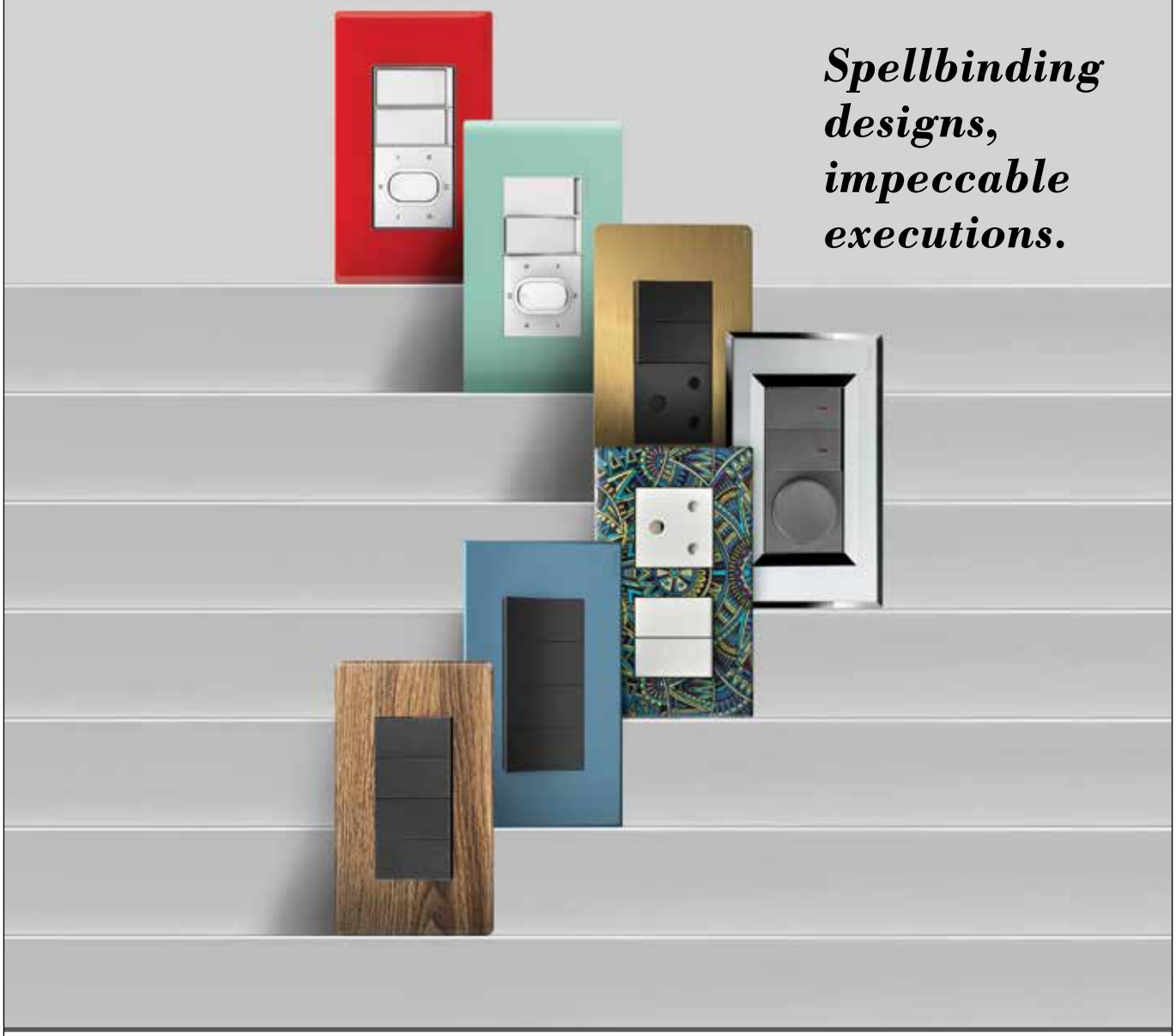
Flat No. 100B, Kasturi Appt., New Nagratoli, Near Women's College, Science Block, Ranchi(Jh.)
Mob. :- 9955165816 | 9199543249, E-mail :- goutammazumdar1@gmail.com, rahul5833@gmail.com


PARROT
सब का विश्वास !
यही है खास !!
Since 1984
पिसे एवं साबुत मसाले
PARROT
Besan
Chakki Atta
Sattu
TARKARI MASALA
CHAT MASALA
Rock Salt
Turmeric Pow
Gota Jeera
AJWAN
AMCHUR POWDER
Hindustan Food Product
Email : parrotmasala1@gmail.com
website : www.parrotmasala.com

kolorsworld.com

KOLORS®
make life better

Spellbinding designs, impeccable executions.





Kolors India Private Limited

401, Vastu Prestige, Sundarban Complex, Link Road, Andheri (W), Mumbai - 400 053

Toll-free : 1800 221 470 | E : sales@kolorsworld.com | Follow us on:

TATA MOTORS
Connecting Aspirations

BAPL
Budhia Agencies Pvt. Ltd.

15 वर्षो से आपकी सेवा में

टाटा मोटर्स के अधीकृत डीलर

बुधिया एजेंसी प्रा. लि.

वाणिज्यिक वाहन की सभी मॉडल के लिए
संपर्क करें



Authorised Commercial Vehicle Dealer of TATA MOTORS LTD.

BUDHIA AGENCIES PVT. LTD.

Booti Nh-33, Ranchi-835 217. Jharkhand

Contact us : +91 72800 55505

OUR BRANCHES : Ranchi, Gumla, Simdega, Lohardaga, Daltonganj, Garhwa, Latehar, Khunti

फेडरेशन ऑफ झारखण्ड चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज
Ph. : 0651-2331250, E-mail : fjccirnc@gmail.com/info@fjcci.org
Website : www.fjcci.org के लिए महासचिव डॉ. अभिषेक रामाधीन द्वारा प्रकाशित, सुनिल सरावगी, अभिषेक अग्रवाल द्वारा संपादित।
केवल निजी वितरण हेतु
Connect us : @fjcciranchi | @FJCCI | www.fjcci.org

•Shreya, Ranchi # 9431100396